



भारत का गज़त The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]
No. 337]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 10, 1989/ज्येष्ठ 20, 1911

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 10, 1989/JYAISTHA 20, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 1989

या चालू रखने को इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थान से उक्त अधिनियम की धारा 35 को उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि यूनाइटेड इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता को मंजूर की गयी अधिस्थान की कालावधि के दौरान, वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना,—

(क) अपने दायत्वा आर बाध्यताओं के नवाहन में या अन्यथा कोई उधार या अधिगम नहीं देगा; कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनियान रहीं करेगा, या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या

इसमें इसके पश्चात् उद्घाटित दिनांक और रीति के सिवाएँ कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा:—

- (1) प्रत्येक बवत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निषेप में जाने वह किसी भी नाम से जात हो, कुल अतिरेक के 50 प्रतिशत से अनधिक राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की बाबत संदर्भ रकम की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रुपये तथा संस्थाओं के मामले में 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी रकम ऐसे किसी निषेपकर्ता संस्था की जो किसी रूप में बैंक का अहंकार है, संदर्भ नहीं को जाएगा।
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संबाय अंतर्गतों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन प्रदूत होता है, असंदर्भ रह जाती है;
- (3) तारीख 10 जून, 1989 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात् बसूल किए गए बिलों की रकम;
- (4) कोई ऐसा व्यय जो उक्त बैंक द्वारा या उसके बिलही फाइल किए गए किसी बाब या अपोल के संबंध में या बैंक द्वारा अनिप्राप्त दिनी के संबंध में या उसको देय किसी रकम को बसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक बाब या अपोल या दिनी या कार्यवाही की बाबत रूप 2500 रुपये से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक को लिखित अनुशा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अधिग्राहित की जाएगी; और
- (5) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी कानूनों के प्रतिविन के प्रत्यासम का संचालन करने के लिए बैंककारी कानूनों की राय में आवश्यक है, परन्तु जहां किसी मद पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व उह कलेंडर मास के दौरान उस मद के मध्ये औत मासिक व्यय से अधिक है या उहां उक्त अवधि के दौरान उस मद के मध्ये कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे में मद पर व्यय 2500 रुपये से अधिक है वही भारतीय रिजर्व बैंक को लिखित अनुशासन के विकास की समाप्ति को जाएगी;
- (6) तारीख 10 जून, 1989 को कारबाह की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुरूप के लिए अद्यता राशि अंतरण या उसका अन्यथा अवधारणा नहीं करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि यूनाइटेड इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता उसे मंजूर की गयी स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संवाद, अर्थात् यूनाइटेड इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता की भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इनके निती सरकारी व्यक्तियों या अन्य प्रतिभूतियों के विहृ उद्यारों/अधिकारी के या विए गए प्रतिशाय के लिए आवश्यक है, और जो उस तारीख को जिसकी अधिस्थगन आदेश प्रदूत होता है, असंबंध है अनिवार्यत संवाद फर सहता है।

4. केन्द्रीय सरकार यह और निवेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान यूनाइटेड इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता पूर्वोक्त संवाद करने के प्रयोजन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुमति नहीं, परन्तु इस आदेश को किसी बात का यह अर्थ नहीं ली जाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने को अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित गर्ने का यूनाइटेड इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निवेश देती है कि यूनाइटेड इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को, जिनकी बसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकबार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा निमित्त लिए गए अनुरोध पर उस दिना में आरत लोटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि यूनाइटेड इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्नलिखित रीति में और विद्यार तक निरुद्ध या परिवर्तन कर सकेगा जो किसी उद्धार, वर्तमान प्रतिवर्त या श्रीवरद्वाप्त के लिए इसके पावत विरवी रखा गया है, आवश्यकता विलंगित या बंत्रु या अन्यथा प्रमारित किया गया है:—

(1) किसी ऐसी बात में विप्रै, याहिरी उद्धार लेने वाले या उद्धार लेने वालों से देय सभी रहनों के मध्ये पूर्व संवाद बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और

(2) किसी अन्य बात में, अनुरोध अनुशासनों या ऐसे अनुपालों से जो अधिस्थगन देश के प्रश्न होने से पूर्व रखे गए थे, इन बोलों में से जो भी उच्चबत्तर हो, नीवे उच्च भाल या प्रतिभूतियों पर सोमाली के अनुपाल को कम किए जिमा ऐसी भाला तक जो आवश्यक या संन्देश हो।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 1989

S. O. 434 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the United Industrial Bank Limited, Calcutta for the period from the close of business on the 10th June, 1989 upto and inclusive of the 10th October, 1989 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the United Industrial Bank Limited, Calcutta shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—

(a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :

(i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000/- and in the case of institutions Rs. 25,000/- and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way ;

(ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force ;

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 10th June, 1989 and realised before, on or after that date ;

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2500/- the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred ; and

(v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar months exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred ;

(b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 10th June, 1989.

3. The Central Government hereby also directs that the United Industrial Bank Limited, Calcutta may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the United Industrial Bank Limited, Calcutta by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the United Industrial Bank Limited, Calcutta shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require

the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the United Industrial Bank Limited, Calcutta.

5. The Central Government hereby further directs that the United Industrial Bank Limited, Calcutta may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the United Industrial Bank Limited, Calcutta may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or

otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft :—

- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally ; and
- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17/2/89-BO-III]

MANTRESHWAR JHA, Jt. Secy.